खण्ड 10, संख्या 4

दिसम्बर 2010 – जनवरी 2011

जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का द्विमासिक न्यूज़लैटर

रायगढ़ कार्यशाला

बस्तर कार्यशाला

सीतापुर कार्यशाला

भारत में जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा रायगढ़ व बस्तर (छत्तीसगढ़) तथा सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में आयोजित ज़िला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशालाएं

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विषयगत क्षेत्रों एवं नेतृत्व कौशल, बातचीत, निगरानी, संरक्षण तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को झेलने की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा बस्तर जिलों में 3 व 4 जनवरी, 2011 एवं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में 29 जनवरी, 2011 को पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

रायगढ़ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, श्री अमर अग्रवाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ ने कहा कि "हमें अपनी युवा शक्ति एवं संसाधनों को मजबूत बनाना है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं समुदाय को जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है तथा समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी हैं, विशेष रूप से पिछड़े एवं आंतरिक क्षेत्रों में।"

बस्तर कार्यशाला का उद्घाटन श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में, श्री उसेंडी ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं एवं वे अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे सरकारी कार्यक्रमों के विकास के प्रति स्थानीय जनता में जागरूकता पैदा करें। उन्होंने आगे इस बात पर बल दिया कि अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण लोग स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में काम करने की तत्काल आवश्यकता है।

श्री रामहेत भारती, निर्वाचन/वजन और माप तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सीतापुर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अपने भाषण में, श्री भारती ने कहा कि "बढ़ती हुई जनसंख्या न केवल क्षेत्र के विकास को रोकती है बल्कि गरीबी में वृद्धि भी करती है, विशेष रूप से कमजोर वर्गों में।"

अधिक जानकारी अन्दर के पृष्ठों पर

छठा सत पॉल मित्तल स्मारक व्याख्यान "विश्व जनांकिकीय परिवर्तन एवं इसके कुछ प्रभाव"

प्रो. टिम डायसन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एंड पालिटिकल साइंसेज द्वारा जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 21 जनवरी, 2011 को छठा सत पॉल मित्तल व्याख्यान दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रो. बी.बी. भट्टाचार्य, उप–कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पी.ए. संगमा, सांसद द्वारा की गयी। प्रो. पी.एम. कुलकर्णी द्वारा प्रो. टिम डायसन एवं श्री पी.ए. संगमा का संक्षिप्त परिचय दिया गया।

अधिक जानकारी पृष्ठ 6 पर

सम्पादक की कलम से

भारत में पंचायतें ग्रामीण स्तर पर शासन संबंधी पुरानी संस्थाएं हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार क्षेत्र, प्राधिकार एवं धन संबंधी अधिकारों की दिशा में मज़बूत किया किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या स्थिरीकरण सहित अनेक विकास संबंधी गतिविधियां सौंपी गयी हैं। सामुदायिक स्तर पर लोगों की ज़रूरतों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं की जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा होती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति–2000 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2001 में ग्रामीण स्तरों पर सेवा वितरण संबंधी विकेंद्रीकरण एवं अभिसरण भामिल है तथा इनकी सुनिश्चितता के लिए इन नीतियों के अंतर्गत पंचायती राज संस्था को एक जिम्मेदार एजेंसी के रूप में मान्यता दी गयी है।

भौगोलिक विषमताओं, सामाजिक अन्याय, महिलाओं की बदतर हालत, अशिक्षा एवं जाति व्यवस्था के बावजूद, प्रत्येक पांच वर्षों में अधिकांश राज्यों में पंचायत चुनाव होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात स्थानीय निकायों में महिलाओं का चुनाव निश्चित रूप से उनकी क्षमता में सुधारों को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रों में, महिला पंचायत राज संस्था सदस्य पोलियो उन्मूलन, स्वास्थ्य शिविरों, सेवाओं हेतु महिलाओं को एकजुट करने तथा कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों के दानदाताओं द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का ध्यान स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ओर केंन्द्रित करने पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समुदाय एवं महिला स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने में सहयोग दिया है, जो पंचायतों की भागीदारी से संबंधित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों में सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना तथा रैफरल परिवहन योजना भी लागू की गयी हैं। इस दिशा में अधिकांश अनुभव सकारात्मक रहे हैं, परन्तु पंचायतों की कार्रवाई की दिशा में अनूकूल वातावरण को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को दुर्गम क्षेत्रों में कमज़ोर तथा जनसाधारण वर्ग तक सेवाओं के विस्तार एवं स्थानीय सरकारी संस्थानों को समाज के निवारक एवं प्रोत्साहक उपायों के साथ संबद्ध करने संबंधी सुनिश्चितता के एक साधन के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना, कार्यान्वयन, एवं निगरानी के लिए पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ग्राम, ब्लॉक एवं ज़िला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी परिणाम पंचायतों के अच्छे कामकाज पर निर्भर करते हैं। जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कामकाज में सहयोग करेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता की कुंजी हैं: अन्तर–क्षेत्रीय अभिसरण, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व एवं निजी क्षेत्र की सहायता से एक सुचारू सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली।

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा विषयगत क्षेत्रों एवं नेतृत्व कौशल, बातचीत, निगरानी, संरक्षण तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को झेलने की क्षमता निर्माण की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर व बस्तर ज़िलों तथा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक अभिविन्यास एवं संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास का मानना है कि बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी को हासिल करने तथा जनसाधारण तथा कमजोर लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और गरीबों तक पहुंचने में केवल पंचायती राज संस्थायें ही एकमात्र जरिया हैं।

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से "विश्व जनांकिकीय परिवर्तन तथा इसके कुछ प्रभाव" नामक विषय पर छठे सत पॉल मित्तल स्मारक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज के प्रो. टिम डायसन द्वारा यह व्याख्यान दिया गया। प्रो. डायसन ने कहा कि भारत में जनांकिकीय संक्रमण लगभग 150 वर्षों – बीसवीं सदी की शुरूआत से लेकर वर्तमान सदी के मध्य तक रहेगा। देश की जनसंख्या में वृद्धि लगभग पांच या छह गुणा के आसपास हो सकती है। यह बहस का मुद्दा है कि क्या यूरोप के अलग–अलग देशों से भारत की तुलना करना उचित है। हालांकि, 1750 से 1950 के बीच इंग्लैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कुछ अधिक थी – लगभग सात या आठ गुणा के आसपास। सापेक्ष संदर्भ में, यूरोप एवं चीन तथा भारत सहित सभी देशों ने अपने जनांकिकीय संक्रमण के अनुभव से अपनी जन्म एवं मृत्यु दरों में संतुलन बनाये रखने में अपेक्षाकृत अत्यधिक प्रगति की।

मनमोहन शर्मा
कार्यकारी सचिव
भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास

विश्व एड्स रोग दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 1.12.2011 को नई दिल्ली में कम प्रचार वाले राज्यों के लिए राष्ट्रीय एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता तथा एड्स रोग के उच्च जोखिम को रेखांकित किया गया

नई दिल्ली, 1.12.2010

विश्व एड्स रोग दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 1.12.2011 को नई दिल्ली में कम प्रचार वाले राज्यों के लिए राष्ट्रीय एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता तथा एड्स रोग के उच्च जोखिम को रेखांकित किया गया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 1.12.2011 को विश्व एड्स रोग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कम प्रचार वाले राज्यों के लिए राष्ट्रीय एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता तथा एड्स रोग के उच्च जोखिम को रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 एड्स महामारी की 30वीं वर्षगांठ है परन्तु भारत ऐसे देशों में से है जिसने नये एचआईवी संक्रमणों में, विशेष रूप से विगत दस वर्षों में उल्लेखनीय कमीं की है। श्री आज़ाद ने संतोष व्यक्त किया कि उनके मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), सहयोगियों के नेटवर्क एवं हजारों कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से एचआईवी के खिलाफ लड़ाई संभव हुई है। मंत्री जी नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बोल रहे थे जब रेड रिब्बन एक्सप्रेस 22 राज्यों की लगभग 25000 किमी. की सफल यात्रा एवं 152 स्टेशनों के लगभग 80 लाख लोगों को जागरूक बनाने के बाद वापस आयी।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विगत दशक में नये एचआईवी संक्रमणों में लगभग 50% वार्षिक दर से अधिक कमीं आयी है। 2000 में 2.7 लाख के मुकाबले, 2009 में भारत में लगभग 1.2 लाख नये एच.आई.वी. संक्रमण थे। राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क एचआईवी व्यापकता दर में 2000 में लगभग 0.41%, 2006 में 0.36% से 2009 में 0.31% की लगातार गिरावट जारी रही। 2009 में अनुमानित 1.2 लाख नये संक्रमणों में, छह उच्च व्यापकता वाले राज्यों का केवल 39% योगदान था, जबकि उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों का नये संक्रमणों में 41% योगदान था।

मंत्री जी ने कहा कि भारत में लगभग 1,15,000 बच्चों के एचआईवी से संक्रमित होने का अनुमान है। "इसलिए सभी संक्रमित बच्चों की तत्काल पहचान करने एवं आवश्यक देखभाल तथा सहायता के साथ उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। हमें मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी व्यापक प्रसार को मज़बूत करना चाहिए। श्री आज़ाद ने दो एचआईवी पीड़ित बच्चों से भी कार्यक्रम स्थल पर मुलाकात की एवं और अधिक एआरटी केंद्र खोलने तथा

श्री गुलाम नबी आजाद, केन्द्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, नई दिल्ली में 1.12.2010 को विश्व एड्स दिवस पर आयोजित समारोह में भाषण देते हुए। इस अवसर पर केन्द्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री दिनेष त्रिवेदी एवं श्री एस. गांधीसेलवन भी उपस्थित थे।

रविवार एवं छुट्टियों में भी इन केंद्रों को खोलने का आश्वासन दिया, ताकि संक्रमित बच्चे विद्यालय जा सकें इस पर विधिवत रूप से ध्यान दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रयास किये जाएंगे। श्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमें एड्स रोग की दृष्टि से सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि "तीन शून्य" का लक्ष्य – शून्य नये एचआईवी संक्रमण; शून्य भेदभाव एवं शून्य एड्स रोग मृत्यु का लक्ष्य सुनिश्चित हो सके।

श्री के. चन्द्रमौली, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पदभार संभालने के बाद आज अपने पहले कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि भारत सरकार ने 5300 से अधिक मेडिकल कालेजों तथा 24–घंटे कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में परामर्श एवं परीक्षण सेवाओं का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक, जिला एवं उप–केंद्र स्तरीय अस्पतालों में 540 लिंक एंटी–रेट्रोवायरल उपचार (एआरटी) केन्द्र लगभग 20,000 एड्स पीड़ित लोगों के घर तक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पंक्ति के 10 उत्कृष्ट एंटी–रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। सचिव व महानिदशक, नाको ने भी बताया कि राष्ट्रीय बाल एड्स पहल की शुरूआत के बाद, अन्य संबंधित देखभाल, सहायता एवं उपचार कार्यक्रमों की राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा शुरूआत की गयी है। एचआईवी / एड्स रोग पीड़ित बच्चों के लिए देश भर में सात क्षेत्रीय बाल स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। एचआईवी / एड्स रोग पीड़ित अनाथ बच्चों के आश्रय एवं सहायता के लिए छह समर्पित सामुदायिक देखभाल केंद्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2010 तक, 76598 बच्चों को पंजीकृत किया गया है एवं 21665 बच्चों को दूसरी पंक्ति के एंटी–रेट्रोवायरल उपचार सहित मुफ्त एआरटी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी एवं श्री एस. गांधीसेल्वन भी रेड रिब्बन एक्सप्रेस कार्यक्रम के समापन समारोह में उपस्थित थे।

भारत की जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एकदिवसीय जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला

रायगढ़, छत्तीसगढ, 3 जनवरी, 2011

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 3 जनवरी, 2011 को पोलिटेकनिक कालेज, चक्रधर रोड़, रायगढ, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर पंचायत राज संस्थाओं/निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने की दिशा में एक ज़िला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि श्री अमर अग्रवाल, मानीय स्वास्थ्य मंत्री ने श्रीमती कृष्णा रविन्दर पटेल, अध्यक्ष ज़िला पंचायत; श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, दिल्ली तथा अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की कार्यवाही शुरू की।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री अमर अग्रवाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया तथा श्रीमती कृष्णा रविन्दर पटेल, अध्यक्ष, ज़िला पंचायत, रायगढ़ द्वारा कार्यशाला की अध्यक्षता की गयी। श्री विष्णु देव साई, सांसद; श्री प्रदीप गांधी, पूर्व–सांसद समन्वयक, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, छत्तीसगढ़; श्री नंद कुमार पटेल, विधायक; डा. सक्राजीत, विधायक, रायगढ़; श्री हृदय राम रथिया, विधायक, लालुंगा एवं श्री ए.के. अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ विशेष अतिथि वक्ताओं में से थे।

कार्यशाला में ज़िला पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक समिति एवं संरपंचों/प्रधानों सहित लगभग 240 पंचायती राज संस्था सदस्य उपस्थित थे।

श्री अमर अग्रवाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं समुदाय को जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा समुदाय, विशेष रूप से पिछड़े एवं आंतरिक क्षेत्र के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। उन्होंने शिक्षा के महत्व एवं स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा विकास क्षेत्र के साथ इसके सीधे संबंध पर विशेष बल दिया। श्री अग्रवाल ने देश में कुपोषण एवं कुपोषण को कम करने के लिए राज्य द्वारा शुरू की गयी "मितानिन" योजना के बारे में भी बातचीत की।

श्री मनमोहन शर्मा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्यों तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा विगत 30 वर्षों में स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा विकास संबंधी क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जागरूक करने की दिशा में किये गये प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर, प्रो. पी.पी. तलवार, तकनीकी विशेषज्ञ, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा राष्ट्रीय गामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित बस्तर ज़िले की सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य पर प्रस्तुतीकरण

दिया गया, जिसका फोकस छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ ज़िले में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं कार्यक्रम परिदृश्य पर था।

प्रस्तुतीकरण के बाद पंचायती राज संस्थाओं के साथ पैनल विशेषज्ञों का खुला अंतः क्रियात्मक सत्र शुरू हुआ। इस परस्पर बातचीत सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचारों का उल्लेख किया। वे खुश थे तथा उन्होंने कार्यशाला की विषयवस्तु की सराहना की तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास से जनसाधारण स्तर पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुरोध किया, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष रूप से जनसंख्या स्थिरीकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन हेतु अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकें।

संवेदीकरण कार्यशाला के दौरान एक महिला सरपंच की राय

वर्तमान समय में जब जीवनयापन की लागत तेज़ी से बढ़ रही है, हमें अपने देश में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं नियंत्रण की दिशा में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बच्चे की बेहतर शिक्षा एवं उसे स्वस्थ रखने के लिए, प्रत्येक परिवार को एक या दो बच्चे के आदर्श परिवार को अपनाना चाहिए। यदि हमारे बच्चे स्वस्थ एवं अच्छी तरह से शिक्षित हैं, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने परिवेश को भी साफ–सुथरा रखना है एवं अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है।

श्रीमती उमा साव, सरपंच, ग्राम पंचायत, सिहा, थाना पोस्ट–ऑफिस कोटसुरा, पुसोर, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

कार्यशाला के प्रतिभागी माननीय अतिथियों के साथ

छठा सत पॉल मित्
विश्व जनांकिकीय संक्रम

प्रो. टि
लंदन स्कूल ऑफ इकोनो
जवाहरलाल ने
नई दिल्ली, 2

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा 21 जनवरी, 2011 को संयुक्त रूप से छठा सत पॉल मित्तल स्मारक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस वर्ष का व्याख्यान प्रो. टिम डायसन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज, इंग्लैंड द्वारा दिया गया। श्री पी.ए. संगमा, सांसद द्वारा इस समारोह की अध्यक्षता की गयी।

प्रो. बी.बी. भट्टाचार्य, उप–कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया एवं व्याख्यान सीरीज़ के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी। प्रो. पी.एम. कुलकर्णी ने प्रो. टिम डायसन एवं श्री पी.ए. संगमा का संक्षिप्त परिचय दिया। प्रो. नंदू राम एवं प्रो. रवि श्रीवास्तव मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे। श्री रजित भारती मित्तल, स्वर्गीय श्री सत पॉल मित्तल के पौत्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में, श्री पी.ए. संगमा, सांसद ने स्वर्गीय श्री सत पॉल मित्तल, सांसद के साथ अपने पन्द्रह वर्षों के निकट सहयोग की याद दिलायी। उन्होंने कहा कि श्री मित्तल एक दूरदर्शी एवं वैश्विक दृष्टि के व्यक्ति थे। श्री मित्तल एवं उनके मित्र स्वर्गीय प्रो. राम लाल

पारिख, सांसद द्वारा संपूर्ण विकास की दृष्टि से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में सांसदों को शामिल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की पहल पर भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास की स्थापना की। उनकी दृष्टि एवं दूरदर्शिता पूरी तरह से उजागर हुई जब उन्होंने इस विशाल कार्य में सभी राजनीतिक दलों को आकर्षित तथा शामिल किया। जनसंख्या एवं विकास संबंधी संसदीय आंदोलन कागज़ी कार्रवाई मात्र रह जाता यदि श्री मित्तल 1980 के बाद से इसमें जीवन का संचार नही करते। एशिया के अलावा, वैश्विक मंच पर भी उन्होंने एक महासचिव के रूप में मानव जीवन रक्षा संबंधी आध्यात्मिक एवं संसदीय नेतृत्व संबंधी गतिविधियों में रूचि दिखायी।

अपना भाषण शुरू करते हुए, प्रो. टिम डायसन ने कहा मैं स्व. श्री सत पॉल मित्तल जैसे महान दूरदर्शी व्यक्ति की याद में आमंत्रित व्याख्यान देने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जिन्होंने जनसंख्या एवं विकास के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने अत्यधिक योगदान दिया है। इस क्षेत्र के अन्य प्रचारकों की तरह ही, उन्होंने भी समग्र एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर जनसंख्या के महत्व को देखा है। उदाहरण के लिए, समग्र स्तर पर जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध है। और, व्यक्तिगत स्तर पर, यहां एक अहम तथ्य है कि आधुनिक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से प्रत्येक महिला द्वारा जन्म नियंत्रण संबंधी सुरक्षित, वहनीय एवं प्रभावी उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। यहां स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए – "संयोग के बजाय, स्वेच्छा से बच्चे।"

अर्न्तराष्ट्रीय परिवार नियोजन आंदोलन के इतिहास के बारे में बातचीत करते हुए प्रो. डायसन ने कहा "यह स्पष्ट है कि कैसे संपूर्ण स्तर पर गरीबी को कम करने एवं व्यक्तिगत तथा घरेलू स्तर पर महिलाओं को अवांछित प्रसव संबंधी दोहरे उद्देश्यों से छुटकारा मिला।"

उन्होंने आगे कहा कि जनांकिकीय संक्रमण तुलनात्मक रूप से एक उपेक्षित विषय है। शायद ही कभी इसका पूरी तरह से अध्ययन किया गया हो। इसके कई प्रभावों का मुश्किल से पता चलता है। जनांकिकीय संक्रमण को कभी–कभी एक साधारण रेखाचित्र के माध्यम से चित्रित किया

ल स्मारक व्याख्यान

ण एवं इसके कुछ प्रभाव

ा
डायसन
स एंड पॉलिटिकल साइंस,
विश्वविद्यालय
जनवरी, 2011

जाता है। वास्तव में, यह एक उच्च शैली है जिसे 'कुख्यात' शैली के रूप में वर्णित किया गया है।

जनांकिकीय संक्रमण के शुरू में, मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों अधिक होते हैं। इसलिए, यहां अपेक्षाकृत कम प्राकृतिक वृद्धि (जनसंख्या वृद्धि) होती है। पहली प्रक्रिया मृत्यु दर में गिरावट है– अर्थात् मृत्यु दर में कमी। यह प्राकृतिक वृद्धि की दूसरी प्रमुख प्रक्रिया का कारण बनती है, जिसमें दर में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि उर्वरता (जन्म दर) मोटे तौर पर कुछ समय के लिए निरंतर बनी रहती है। हालांकि, एक अंतराल के बाद, जन्म दर में गिरावट आती है और प्रजनन क्षमता में गिरावट जनांकिकीय संक्रमण की तीसरी प्रमुख प्रक्रिया है।

श्री रजित भारती मित्तल (सबसे दांये), स्व.श्री. सतपॉल मित्तल के पौत्र, श्री पी.ए. संगमा का स्वागत करते हुए।

यहां इस बारे में काफी बहस की गयी है कि प्रजनन क्षमता में उच्च से निम्न स्तरों की गिरावट क्यों होती है। यह स्पष्ट है क्योंकि कई कारक – उदाहरण के लिए जैसे – आर्थिक स्थितियां, धार्मिक मान्यताएं, शैक्षिक स्तर, सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम इसको प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, यह कहना उचित है कि जिन विद्वानों ने इस प्रक्रिया पर विस्तार से विचार किया है उनमें से अधिकतर मृत्यु दर में गिरावट को आखिरकार मानते हैं – जो प्रजनन क्षमता में गिरावट का 'असंबद्ध' कारण है। इस प्रकार जैसे कि जॉन कास्टरलिन ने कहा है: प्रजनन क्षमता में गिरावट व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के तहत होती है परन्तु वास्तव में मृत्यु दर में गिरावट के अभाव में कभी नहीं, तथा इसे एक पुख्ता सबूत है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता मं गिरावट का प्रमुख कारण है।"

बातचीत के अंत में प्रो. डायसन ने भारत में जनांकिकीय संक्रमण से संबंधित कुछ रोचक निश्कर्षों के बारे में बताया।

भारत में जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एकदिवसीय ज़िला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला

बस्तर, छत्तीसगढ़

4 जनवरी, 2011

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की दिशा में जागरूक करने के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 4 जनवरी, 2011 को कलेक्टोरेट सभागार, जगदलपुर ज़िले (छत्तीसगढ राज्य) में पंचायती राज संस्थाओं/निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए एक ज़िला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ ने श्री लच्छू राम कश्यप, अध्यक्ष, ज़िला पंचायत; श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास दिल्ली तथा अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला की कार्यवाही शुरू की।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया एवं इसकी अध्यक्षता श्री लच्छू राम कश्यप, अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा की गयी। श्री प्रदीप गांधी, समन्वयक, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास (छत्तीसगढ); श्री सुभाउ कश्यप, विधायक, बस्तर; श्री संतोष बाफना, विधायक; श्री बेदू राम कश्यप, विधायक; श्री किरन देव, महापौर, नगर निगम; श्री तरूण चोपड़ा, उप–महापौर, नगर निगम; श्री रूप सिंह मंदारी, अध्यक्ष, जनपद बस्तर; श्री यशवन्त राव, विपक्ष के नेता, नगर निगम; श्री एम.एस. परास्ते, ज़िलाध्यक्ष, बस्तर एवं डा. प्रसन्ना, सीईओ, ज़िला पंचायत विशेष अतिथिवक्ताओं में से थे।

ज़िला पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक समिति एवं सरपंचों/प्रधानों सहित लगभग 190 पंचायती राज सदस्य इस कार्यशाला में उपस्थित थे।

श्री विक्रम उसेंडी, माननीय वन मंत्री, छत्तीसगढ़ ने पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए छत्तीसगढ़ के पिछड़े तथा दूरस्थ ज़िले में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी मुद्दों पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए बधाई दी। निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय जनता से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं तथा वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। स्थानीय जनता में सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने आगे ज़ोर देते हुए कहा कि अशिक्षा तथा जागरूकता की कमीं के कारण लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं

हैं जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में तत्काल काम करने की जरूरत है।

श्री मनमोहन शर्मा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्यों तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा विगत 30 वर्षों में स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा विकास संबंधी क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जागरूक करने की दिशा में किये गये प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर, प्रो. पी.पी. तलवार, तकनीकी विशेषज्ञ, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा राष्ट्रीय गामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित बस्तर ज़िले की सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य पर प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसका विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य के बस्तर ज़िले में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं कार्यक्रम परिदृश्य पर था। इस प्रस्तुतीकरण पर प्रतिभागियों ने अच्छी तरह से अपनी सहमति जताई।

श्री प्रदीप गांधी, पूर्व–सांसद व समन्वयक, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, छत्तीसगढ़, ने प्रतिभागियों को बताया कि रायगढ़ के बाद बस्तर ज़िले को इस कार्यशाला के आयोजन का सौभाग्य मिला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के आयोजन के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधि समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के काम में निश्चित रूप से अधिक उत्साह के साथ जागरूक तथा प्रोत्साहित होंगे। यह कार्यशाला अंतरालों को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

प्रस्तुतीकरण के बाद पंचायती राज संस्थाओं के साथ पैनल विशेषज्ञों का खुला बातचीत सत्र शुरू हुआ। इस बातचीत सत्र के

दौरान प्रतिभागियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कार्यशाला की विषयवस्तु की सराहना की तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास से इस तरह की कार्यशालाओं को जनसाधारण स्तर पर आयोजित करने का अनुरोध किया, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष रूप से जनसंख्या स्थिरीकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन हेतु अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें।

अध्यक्ष, ज़िला पंचायत, बस्तर का पत्र

मैं पंचायती सदस्यों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास को बधाई देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रमों की तत्काल जरूरत है ताकि इन क्षेत्रों के लोग जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे एवं अपने परिवारों के आकार को सीमित कर सकेंगे।

श्री लच्छू कश्यप, अध्यक्ष, ज़िला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

कार्यशाला के प्रतिभागी

भारत में जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एकदिवसीय ज़िला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला

सीतापुर, उत्तर प्रदेश

29 जनवरी, 2011

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की दिशा में जागरूक करने के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 29 जनवरी, 2011 को सीतापुर नेत्र अस्पताल सभागार (उत्तर प्रदेश) में पंचायती राज संस्थाओं/निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए एक ज़िला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि श्री रामहेत भारती, निर्वाचन/माप–तौल एवं उपभोक्ता मंत्री, उत्तर प्रदेश ने श्रीमती उषा भारती, अध्यक्ष, ज़िला पंचायत, सीतापुर; श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास, दिल्ली तथा अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला की कार्यवाही शुरू की।

श्री रामहेत भारती, निर्वाचन/माप–तौल एवं उपभोक्ता मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया तथा श्रीमती उषा भारती, अध्यक्ष, ज़िला पंचायत, सीतापुर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गयी। श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर; डा. विजय शंकर राय एवं डा. बी.के. वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर विशेष अतिथि वक्ताओं में थे।

जिला पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक समिति एवं सरपंचों/प्रधानों सहित लगभग 170 पंचायती राज सदस्य इस कार्यशाला में उपस्थित थे।

श्री रामहेत भारती ने पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जैसे पिछड़े ज़िले में जनसंख्या स्थिरीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने के लिए बधाई दी। निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय जनता से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं एवं वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। स्थानीय जनता में सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने आगे ज़ोर देते हुए कहा कि अशिक्षा एवं जागरूकता की कमीं के कारण लोग स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में तत्काल काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी कि बढ़ती हुई जनसंख्या न केवल क्षेत्र के विकास में बाधक है बल्कि यह विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों की गरीबी में वृद्धि का भी कारण है। उन्होंने आगे कहा कि छोटा परिवार ही बेहतर स्वास्थ्य की दौलत हैं। श्री हृदय शंकर तिवारी, सीडीओ, सीतापुर ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या माँ एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है।

कार्यशाला के आरम्भ में श्री मनमोहन शर्मा ने सभा का स्वागत किया एवं प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्यों तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा विगत 30 वर्षों में स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा विकास संबंधी क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जागरूक करने की

दिशा में किये गये प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संकेतकों के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण एवं स्वास्थ्य परिदृश्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे निम्न/धीमा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है, इसलिए इस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर, प्रो. सुदेश नांगिया, तकनीकी विशेषज्ञ, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर सीतापुर जिले की सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसका ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर ज़िले में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं कार्यक्रम परिदृश्य पर केंद्रित था। इस प्रस्तुतीकरण पर प्रतिभागियों ने अपनी सहमति जताई।

प्रस्तुतीकरण के बाद पंचायती राज संस्थाओं के साथ पैनल विशेषज्ञों का खुला बातचीत सत्र शुरू हुआ। इस बातचीत सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचारों का उल्लेख किया। वे खुश थे एवं उन्होंने कार्यशाला की विषयवस्तु की सराहना की तथा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास

से इस तरह की कार्यशालाओं को जनसाधारण स्तर पर आयोजित करने का अनुरोध किया, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष रूप से जनसंख्या स्थिरीकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन हेतु अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें।

एक पंचायत सदस्य द्वारा दिये गये कुछ सुझाव

- प्रत्येक गांव में एक उप–स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए।
- प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित जन्म परिचारिका (दाई) उपलब्ध होनी चाहिए।
- ग्राम पंचायत में एएनएम उपलब्ध होनी चाहिए।
- प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र एवं मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होनी चाहिए।
- गर्भनिरोधकों का मुफ्त वितरण।
- नियमित अंतराल पर टीकाकरण शिविर।
- स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत सदस्यों की सामयिक बैठकें।
- स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निगरानी दौरे।
- गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता।

श्री विनोद कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत विलरिया, पोस्ट–ऑफिस भंडिया, तहसील सिधोली, ज़िला सीतापुर।

कार्यशाला के प्रतिभागी

प्रभारी मंत्री उसेंडी द्वारा कार्यशाला
www.navabharat.org
जगदलपुर-दंतेवाड़ा
कार्यशाला
पहला कॉलम
ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम पर हुई
दण्डकारण्य समाचार
स्थानी
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों
वेदीकरण कार्यशाला
भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु छत्तीसगढ़ के रायपुर व बस्तर ज़िलों तथा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आयोजित ज़िला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला ने व्यापक मीडिया कवरेज को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास में उपस्थित हम सभी का विश्वास है कि इससे बड़े पैमाने पर समुदाय की भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में विकास का फल सीमांत तथा कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं गरीबों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल कार्यशाला का करेंगे शुभारंभ
प्रभारी मंत्री श्री उसेण्डी ने दीप प्रज्वलित कर
जागरण सि
जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्
ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित टिप्
दिए पंचायत प्रतिनिधियों को
जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला
ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम पर हुई कार्यशाला
जनसंदेश
सम्पादक
मनमोहन शर्मा
जनसंदेश एक द्विमासिक प्रकाशन है
भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास
(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शी स्थिति)
1/6, सीरी इन्सटीटयूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली–110049
टेलिफोनः 011–41656661/68/69 फैक्सः 011–41656660
ई.मेलः iappd@airtelmail.in
Asha Enterprises, 9811854631